processing for creating value addition in agriculture. The Plan also lays special emphasis to the employment generation programmes in the rural areas.

Autonomy to Cooperative Sector

1545. SHRI VITHAL BHAI M. PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to give more autonomy to the cooperative sector in the changed circumstances;

(b) whether there is any proposal to set up a National Cooperative Bank, an apex body for the cooperative banking sector;

(c) what is the proposal of Government with regard to giving more autonomy to the cooperatives in different fields;

(d) whether any committee was formed to go into the matter if so, whether it has submitted its report; and

(e) by when Government are going to implement the report, if any?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) to (e) Cooperation being a State subject, the Central Government may only initiate steps for policy formulation. The major steps, including the reformulation of their Cooperative Societies Acts in the direction of giving autonomy to cooperatives will have to be taken by the State Governments. However, Government of India have decided to formulate National Policy of Cooperatives. A Committee known as the Committee on "Model Cooperatives Act" was set up by the Planning Commission. The Committee submitted its report which has been circulated to the State Governments for follow up action. The Central Government have initiated steps to reformulate the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 to give a lead to the State Governments to reformulate their cooperative legislations.

Setting up a National Technology Development Corporation

1546. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a National Technology Development Corporation for commercial transfer of technology developed at the Indian Council of Agricultural Research; and

(b) if so, what are the objectives of the proposed National Technology Development Corporation with details thereof?

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) A proposal to constitute a separate Autonomous Body for commercialisation of agriculture technology/products is under consideration.

Subsidy given to Agricultural Sector

1547. SHRI SOM PAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state what is the total amount of subsidy given per annum to agricultural sector through fertilizer, irrigation, electricity and food?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): Sector-wise subsidies are decided by the Ministry of Finance taking a macro view of the economy. The information will be collected and laid on the Table of the Sabha.

बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

1548. **श्री अजीत जोगी:**
चौधरी हरि सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त राशि का पूरा उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

होप्स का उत्पादन

1549. **श्री सुशील बरोंगपा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने होप्स के आन्तरिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई निश्चित उपाय किए हैं;

(ख) क्या देश में होप्स का कुल आन्तरिक उत्पादन इसकी कुल मांग को पूरा कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक सम्भव हो पाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हाँ । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश में होप्स के विकास हेतु 1992-93 के दौरान 51.33 लाख रुपए दिए । खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने भी हिमाचल प्रदेश में 1991-92 के दौरान होप्स के विकास और प्रसंस्करण हेतु 40 लाख रुपए की अनुदान-सहायता दी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उद्योग की होप्स सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकता लगभग 500 मी॰ टन है, जबकि कुल उत्पादन लगभग 250 मी॰ टन है । केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों की प्रगति से देश 1996-97 तक घरेलू आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करने में समर्थ हो जाएगा ।

Agricultural University In North-East Region of Country

1550. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) Whether construction work of the Agricultural University proposed to be set up in the East-Northern States, has commenced; and

(b) If so, by when this University is likely to start functioning and what arrangements have so far been made in this direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) The construction work of the Central Agricultural University for NEH Region has not yet been started.

(b) The Vice-Chancellor of the University has been appointed and as soon as he assumes charge, the university would start functioning.

कृषि का विकास और किसानों का कुशल प्रबन्धन

1551. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के विकास और किसानों के सुप्रबंधन के संबंध में कृषि समिति, 1991-92 की पांचवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सिफारिश सं॰ 1

1.4 समिति ने देखा है कि मानवीय तथा पशुधन की संख्या के दबाव के कारण इतने बड़े क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रणाली चिन्तनीय दर पर खराब हो रही है और इसलिए व्यापक वर्षा सिंचित भूमि पर पारिस्थितिकीय संतुलन की पुनर्बहाली देश के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

1.8 इस तथ्य को देखते हुए कि वर्षा सिंचित क्षेत्र कुल सकल घरेलू उत्पाद के 9.0% का योगदान करते हैं और कृषि के सकल घरेलू उत्पाद के 25.7% का योगदान करते हैं और लगभग 42.2 प्रतिशत जनसंख्या वर्षा सिंचित खेती प्रणाली से आजीविका चलाती है, समिति सरकार से पुरजोर सिफारिश करती है कि वे देश की अस्थिर कृषि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिये वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पनधारा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा आर्थिक व्यवस्था के समुत्थान की प्रक्रिया आरम्भ करें ।

इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा निर्यात के सुधार के लिए वर्षा सिंचित खेती की महत्वपूर्ण भूमिका तथा अत्यधिक सम्भावनाओं को देखते हुए समिति सिफारिश करती है कि वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास पूर्वानुमेय समयसीमा के अन्दर किया जाना चाहिए ।

कार्यवाही:—

1.4 इस समय चल रही पनधारा विकास परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य देश के विशाल वर्षापोषित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनर्बहाली करना है ।

कार्यवाही:—

1.8 पनधारा विकास कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । आठवीं योजना में वर्षापोषित क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा कई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ चलाई जा रही है । इस समय वर्षापोषित क्षेत्रों